

Allocation of Funds Under NREP

4864. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there have been shortfalls in the allocations made for National Rural Employment Programme during 1981-82 and 1982-83 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to make up those shortfalls in allocation for NREP ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन धन का उपयोग

4865. श्री हरीश रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के शैलबस के अधीन कार्यों पर डी.आर.डी.ए. की स्वीकृति का बिना खर्च किये जा रहे धन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के शैलबस का पता लगाने के लिए विकास खंडों से भी परामर्श किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में लोगों के प्रतिनिधियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह देगा ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जिला स्तर पर गठित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों जिनमें सांसदों एवं विधायकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजना तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा जाता है । स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गयी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें "शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स" तैयार करनी होती है तथा उस आधार पर वार्षिक कार्रवाई योजना बनानी होती है । निर्माण कार्यों के चयन तथा शेल्फ ऑफ परियोजना तैयार करने के कार्य में खंडों को भी शामिल किया जाता है ।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को मुआवजा

4866. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को आबंटित भूमि से "शापिंग सेन्टर्स" के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली प्रशासन द्वारा नीलाम की जाने वाली भूमि के लिये इन सोसाइटीज के कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शापिंग सेन्टर्स के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि का ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को मुआवजे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को आवंटित भूमि में से कोई विपणन केन्द्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shifting to NDDB from Anand to Karnal

4867. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether Government have taken a decision to shift National Dairy Development Board from Anand to Karnal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : There is no proposal to shift the National Dairy Development Board from Anand to Karnal.

Increase in Acreage Under Oilseeds and Pulses

4868. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether prices of oilseeds and pulses have gone up in recent months :

(b) whether there is a great need for raising the acreage under oilseeds and pulses to achieve self-sufficiency in edible oils ; and

(c) if so, the total acreage under oilseeds and pulses out of the total cultivable land and the measures taken to raise the acreage under oilseeds and pulses ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) In recent months, particularly since January, index numbers of wholesale prices of oilseeds and pulses have registered a declining trend.

(b) To achieve increases in the pulses and oilseeds production, Government is following a two-pronged approach in increasing the productivity per hectare as well as extending the acreage under cultivation.

(c) The total acreage under oilseeds and pulses in India during 1982-83 was as follows :

(million hectares)

Year	Pulses	Oilseeds
1982-83	22.39	19.10

The measures being taken to increase acreage under pulses and oilseeds and their productivity include introduction of pulse crops in irrigated areas, bringing additional areas under short-duration varieties of moong and urad in summer season and in rice fallows by utilising the residual moisture in rabi season, inter-cropping of arhar with soyabean, bajra, cotton and other crops, multiplication and use of improved seeds of pulses, use of phosphoric fertilizers and rhizobium culture and adoption of plant protection measures, improved post-harvest technology and price support. Similarly, for increasing the production of oilseeds a number of programmes have been taken up, including launching of special projects in potential areas (e.g. groundnut in Saurashtra, soyabean in Madhya Pradesh), emphasis on development of non-traditional oilseeds like sunflower and soyabean, increase in area under irrigated oilseed crops, adoption of improved package of practices including seeds, phosphatic fertilisers and plant protection measures, organisation of composite demonstrations, distribution of mini-kits and price support operations.

Provision of Drinking Water to Problem Villages in Gujarat

4869. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of drinking water problem villages in Gujarat as on April 1, 1983 ;

(b) the number of problem villages provided with safe sources of water as on April 1, 1983 ;

(c) the number of problem villages which remain to be provided with drinking water facility as on April 1, 1983 ; and